नेट-मीटरिंग क्या है? - जानिए इस तकनीक के बारे में हर ज़रूरी बात

भारत में जैसे-जैसे लोग सोलर एनर्जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वैसे-वैसे "नेट-मीटरिंग" शब्द भी तेजी से चर्चा में आ गया है। लेकिन आम आदमी के लिए यह शब्द अभी भी थोड़ा जटिल और तकनीकी लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि **नेट-मीटरिंग क्या है**, यह कैसे काम करता है, और इससे क्या फायदे हैं, तो यह लेख आपके लिए ही है।

नेट-मीटरिंग क्या है?

नेट-मीटरिंग एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अगर आप अपने घर या व्यवसाय पर सोलर पैनल लगाते हैं और वह आपके उपयोग से ज्यादा बिजली उत्पन्न करता है, तो उस अतिरिक्त बिजली को बिजली विभाग (डिस्कॉम) को भेजा जा सकता है। इसके बदले में आपके बिजली के बिल से उतनी यूनिट की कटौती कर दी जाती है।

नेट-मीटरिंग को हिंदी में "शुद्ध माप प्रणाली" कहा जा सकता है, जिसमें आपका मीटर आपके द्वारा खपत की गई और भेजी गई बिजली का अंतर निकालता है।

नेट-मीटरिंग का काम करने का तरीका (कैसे काम करता है?)

इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं:
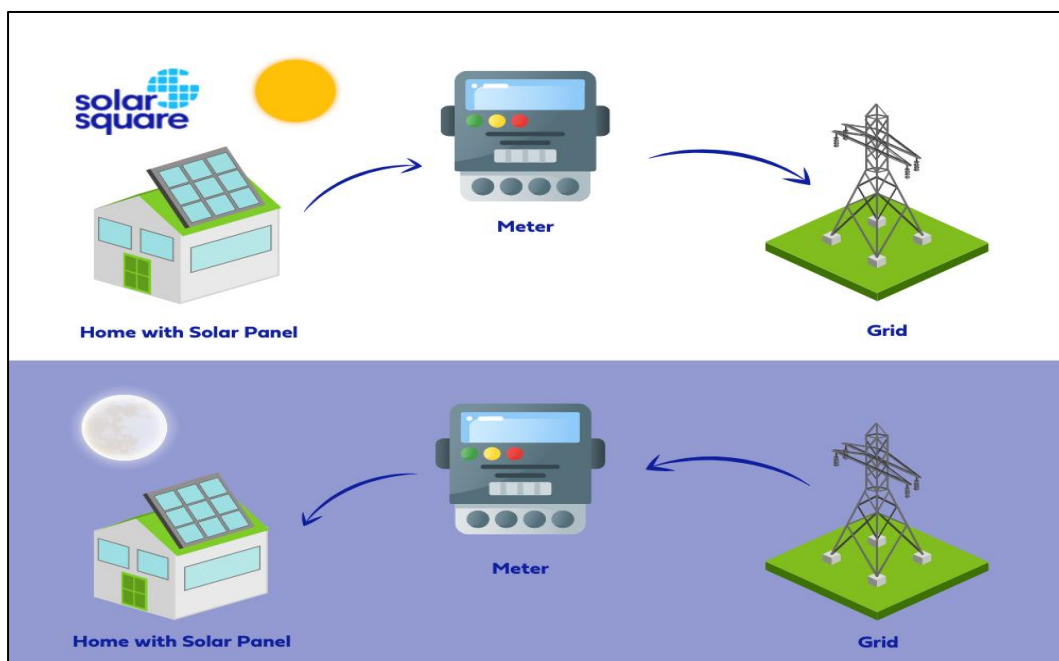
मान लीजिए आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है।

- दिन के समय सोलर पैनल 15 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है।

- आप उस दिन सिर्फ 10 यूनिट बिजली उपयोग करते हैं।
- अतिरिक्त 5 यूनिट बिजली ग्रिड में भेज दी जाती है।
- अब रात में या बाद के समय जब सूरज नहीं है, आप ग्रिड से 6 यूनिट बिजली लेते हैं।
- नेट-मीटर यह मापेगा कि आपने 5 यूनिट भेजी और 6 यूनिट ली, तो सिर्फ 1 यूनिट का ही भुगतान करना होगा।

इसलिए, नेट-मीटरिंग क्या है? यह समझें कि यह एक "give and take" प्रणाली है, जहां आपका सोलर सिस्टम ग्रिड से जुड़ा रहता है, और बिजली की बचत सीधे आपके बिल में दिखाई देती है।

नेट-मीटरिंग की तकनीकी प्रक्रिया
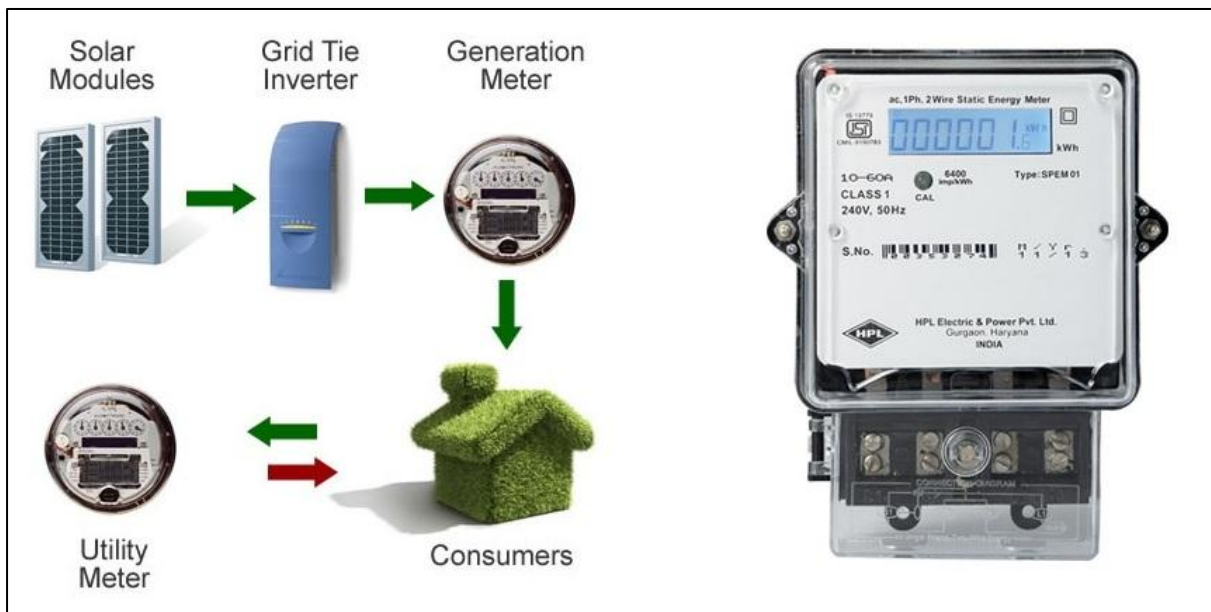
1. नेट-मीटर की स्थापना – बिजली विभाग द्वारा एक विशेष मीटर लगाया जाता है जो दोनों दिशाओं में बिजली के प्रवाह को मापता है।
2. बिजली का बैलेंस – आपकी खपत और उत्पादन का हर महीने मिलान किया जाता है।

3. बिल में समायोजन – महीने के अंत में नेट यूनिट के आधार पर बिल बनाया जाता है।

नेट-मीटरिंग के प्रमुख लाभ

1. **बिजली बिल में भारी कमी** – जितनी ज्यादा बिजली आप उत्पन्न करेंगे, उतनी कम आपको खरीदनी पड़ेगी।
2. **अतिरिक्त बिजली की बर्बादी नहीं होती** – वह ग्रिड में जाकर अन्य उपभोक्ताओं को दी जाती है।
3. **लंबे समय की बचत** – सोलर सिस्टम की लागत कुछ सालों में निकल आती है और फिर फ्री बिजली।
4. **ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा** – कोयला और डीज़ल से बनी बिजली पर निर्भरता घटती है।
5. **सरकारी सब्सिडी और समर्थन** – कई राज्यों में नेट-मीटरिंग को लेकर प्रोत्साहन योजनाएं हैं।

नेट-मीटरिंग कैसे प्राप्त करें?

अगर आप नेट-मीटरिंग शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1. स्थानीय डिस्कॉम की वेबसाइट पर आवेदन करें।
2. अपना सोलर सिस्टम और इन्वर्टर BIS अप्रूव्ड और MNRE द्वारा अनुमोदित रखें।
3. डिस्कॉम निरीक्षण करता है और फिर नेट-मीटर इंस्टॉल करता है।
4. अब आपकी यूनिट का बिलिंग नेट-मीटरिंग के अनुसार होगी।

भारत में नेट-मीटरिंग की स्थिति और नियम

भारत सरकार ने 2021 में Revised Net-Metering Policy जारी की थी, जिसमें कुछ नियम लागू किए गए:

- 500 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए नेट-मीटरिंग की अनुमति।
- कुछ राज्यों में यह सीमा 10 किलोवाट या 50 किलोवाट भी हो सकती है।
- 1 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए ही नेट-मीटरिंग आमतौर पर उपलब्ध है।
- नेट-मीटरिंग के लिए अलग से एग्रीमेंट भी साइन करना होता है।

क्या हर कोई नेट-मीटरिंग का लाभ ले सकता है?

हाँ, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं:

- आपकी छत या ज़मीन पर पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- वहां पहले से कोई अन्य नेट-मीटरिंग कनेक्शन न हो।
- स्थानीय बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) की सहमति आवश्यक होती है।

निष्कर्ष:-

अब तक आपने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि नेट-मीटरिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है। आज के दौर में जब बिजली महंगी होती जा रही है और पर्यावरण संकट बढ़ता जा रहा है, नेट-मीटरिंग एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान है। यह न सिर्फ आपके बिजली बिल को कम करता है, बल्कि भविष्य के लिए एक हरित और स्वच्छ विकल्प भी प्रदान करता है।अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने की सोच रहे हैं, तो नेट-मीटरिंग को जरूर अपनाएं - यह एक बार का निवेश है जो सालों तक फायदे देता है।

For more information visit here: 👉https://sampurnasolar.com/👈